



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2018/पौष 25, 1939

No. 203]

NEW DELHI MONDAY, JANUARY 15, 2018/PAUSHA 25, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2018

का.आ.229(अ)—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

और, थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम के लुंगलेई जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 180.0 वर्ग किलोमीटर है;

और, यह अभयारण्य उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ की जलवायु उप-उष्णकटिबंधीय है। यहाँ वार्षिक वर्षा औसत 1700 मि.मी. से 3900 मि.मी. है। घाटियों और तलहटियों के अलावा यहाँ का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है। यहाँ 70% ढलान और खड़े ढलान हैं और 30% सामान्य ढलान रेतीली मिट्टी और तलछटी चट्टानों वाले हैं;

और, इस अभयारण्य के पारिस्थितिकी, वानस्पतिक, जीवजन्तु संबंधी और प्राकृतिक महत्व के कारण और वन्यजीवों एवं इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसार और विकास के लिए इसकी आवश्यकता को देखते हुए मिजोरम राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत अधिसूचना सं. बी.12012/24/2014-एफएसटी, दिनांक 2 नवम्बर, 2015 के द्वारा इसे अभयारण्य घोषित किया गया था;

और, अभयारण्य अत्यधिक जैव विविधता समृद्ध है, और कई दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) और स्थानिक प्रजातियों का आश्रय और संरक्षण स्थल है;

और, अभयारण्य वनस्पतियों की लगभग 48 प्रजातियों को संरक्षण और आश्रय देता है जिनमें 32 वृक्ष प्रजातियां, 9 झाड़ी प्रजातियां, 2 बांस और रँतन प्रजातियां और 5 ऑर्किड प्रजातियां सम्मिलित हैं। 32 वृक्ष प्रजातियों में अर्डा (*पिथेकोलांबियम बिगोमिनम*), खावीतर (*ड्रायप्टस लैंकीफोलिया*), सपर (*लिंगरा नेकुसुआ*), टायर (*सैरानिया पुंडुआना*), थिंगप्यूथिंग (*लिथोकारपस एलिगेंस*), सापुट (*रैन्डिया वालिची*), थिंगसिया (*कास्टानोपसिस लैंसेफोलिया*), देन (*क्वार्कस हेलिफेरियाना*), हर्से (*मेसुआ फेरेआ*), तेई पुई (*तुना सिलिएट*), थकथिंग (*सिनामोमम वर्म*), सेंटीजेल (*कैलाँफिलेम पेलीथुम*), थिंगलुंग (*एलाकोकार्पस फ्लोरिबुन्डस*), नेल्छचुन (*एरियोबोट्रिया बेंगलेंसिस*), टेस्पाटा (*सिनामोमम तमला*), जथुहांग (*पाँलिलिथिया जेनकिन्सी*), थिंगथुपुइ (*डायोएक्सिलियम गोबारा*), थेई केल एक (*एल्युओकार्पस एरिटाटस*), हन्ना थाप पा (*कोलोनाफला ग्रोकार्पा*), चार (*टर्मिनलिया मेरिओकार्पा*), मौल्हाविह (*सरका एसोका*), पा खाट (*एक्टिनोडापहे-ओडोराटा*), सुकटलॉन्ग (*ममेया सुरिगा*), हमर हलेंग (*स्टैरैक्स सररीरुलाटुम*), लेंनमुई (*साइज़ीयम कुमिनी*), थेई कुम (*डायोस्पीरोज़ मलाबेरिका*), थिहेलेई खाक (*असूरो चित्तागोंगा*), बेराव (*कैनेरियम स्ट्रीकटम*), बनफ़र (*एन्थोसेफ्लुस चिनेसिसिस*), थिंगखिम (*एसर लाविगैटम*), हैफावंग (*मंगिफेरा सिल्वाटिका*) और तुइराम (*टर्मिनलिया क्रेनुलाटा*) शामिल हैं। 9 झाड़ी प्रजातियों में झॉन्गवाहुलंग (*अल्चोर्निया टीलियाफ़ोलिया*), फाकटेल (*ब्रैडेलिया मोनोईका*), केल्टेबेंगबेह (*तबेरनेरामोंटाना डिवरीकेटा*), पेल (*ग्रटम गेन्नमोन*), अरंगेंग (*मेसा इंडिका*), कावलकर (*लीआ इंडिका*), छवातन (*फेजरलिन्डिया फासीक्यूलेट*), लम (*मोरिंडा एगस्टिफ़ोलीया*) और नूनूर (*अर्दिसिया पैनिकुलाटा*) शामिल हैं। बांस की 2 प्रजातियों में माउ ताक (*मेलोकाना बासीफेरा*) और सिरील (*डिनोचलोआ कैम्पैक्टफ्लोरा*) शामिल हैं। ऑर्किड की 5 प्रजातियों में सेनहरी (*रेणेंथेरा इम्बुचुतियाना*), बान सेई/लाईहेंग (*डेंड्रोबियम फ़िम्ब्रियाटम*), लाह लेई (*वांडा कोरुले*), नाउबान पर वर (*कोलॉजीने निटिडा*) और नाउबान-नवी-नाक (*प्लेयोन प्रैक्स*) शामिल हैं;

और, यह अभयारण्य 18 जीव प्रजातियों का शरण स्थल है यहां 4 मांसाहारी प्रजातियां, अनगलित की 2 प्रजातियां, 3 सर्वाहारी प्रजातियां, 4 प्राइमेट प्रजातियां और स्तनधारियों की तीन अन्य छोटी प्रजातियां पायी जाती हैं जिनमें सामान्य तेंदुआ (*पैन्थेरा पार्डस*), गोल्डन बिल्ली (*कैटपूमा टेंमिन्की*), जंगल बिल्ली (*फेलिस चाँस*), तेंदुआ बिल्ली (*प्रियोनायलुरस बेंगलेंसिस*), मुंजक (*मुनटिकस मुंटजैक*), सेरो (*नामोरहेडस सुमात्रांसिस*), एशियाई काला भालू (*उर्सस थिबेटनस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), जंगली कुत्ता (*क्यूओन अल्पाइंस*), कैण्ड लंगुर-नगौ (*प्रेस्विटीस पिलेटस*), हूलाँक गिबबन-हौहुक- (*हीलोबेट हूलाँक*), स्लो लोरियां (*निक्किबस बेंगलेंसिस*), फैरेस लिफ

बंदर (ट्रैक्टीपिटेकस पाइलैटस), हिमालयन क्रेस्टलेस साही-साकुह (हाइस्ट्रीक्स ब्राच्यूरन) मलायना विशालकाय गिलहरी-अतारंग (रतुफा बाकोलोर), हिमालयन धारीदार गिलहरी (टेमीओप्स मैकक्लेलैंडी), माउंटेन कछुआ (मनोरिया एमीज़) और बरमेसे पायथन (पायथन मोलुर्स) शामिल हैं ;

और, यह अभयारण्य पक्षियों से भी समृद्ध है और 38 प्रमुख पक्षी प्रजातियों को आश्रय देता है जिनमें तहहेक-ब्लैक चिन्नड यूहिना (युहिना निग्रिमेटा), देईकत-गोल्डन हेडर्ड टेलरबर्ड (ऑर्थोटॉमस क्यूकुलेटस), थ्लेकबुर-लार्ज वुड लहटोरा (टेफ्रोडोर्निस वीरगाटस), बाउंग-येलो थ्रोटेड मिनेवेट (पिक्रिकोकस सोलरिस), इरललिक / बावंगप्यूई-बडे कोयल-लहटोरा (कोरासिना नोवे-हॉलैंडिया), थ्लोहसाई-ग्रेट स्लेटी कठफोडवा (मुलरिपिकस पेल्वरुलेंटस), सुकलेट-वेलवेट-फ्रंटेड नटहैटच (सिता फ्रॉटिलिस), सुकलेट-व्हाईटबेटेडेड नटहैटच (सिता हिलायनसिस), लुआंगट्यूउबु-स्पीलेट पिकलेट (पिकमुस इनोमिनेटैटस), वसीर-ग्रे सिबिआ (हेटोरोफैसिया ग्रासिलिस), ज़ोवा-स्ट्रीप्ड लाफिंग थ्रस (गरलुलेक्स वर्गाटास), वाबक-हॉजसन के फ़ोगमाउथ (बैट्रेचेस्टोमस हॉजसाँनी), ज़ोचिपुइ-ग्रे विंगेड ब्लैकबर्ड (टर्डस बुलबुल), टेप-हिमालयन ग्रीन फिंच (कार्डुएलिस स्पिनॉयड), हन्नाफ़न-गोल्डन हेडेड टेलोर बर्ड (ऑर्थोटॉमस कुक्कुलस) तहांगै-बे उल्लू (फोडीलस बैडीस), हम्चहे-अरप्यूई पिग्मी ब्रेन-बब्लर (नोएपेगा प्यूज़िला), वलांबॉक-ग्रेट एरेड मोजेर्जर (यूरोस्टोपोगस मैक्रोटीस), लेन्डर-एशी स्वालौव-लहटोरा (एटामास फ्यूस्कस), वामूर-पाम शिफ्ट (साइप्सियसस पैरावस), काब्लॉक-ब्रेथेड हॉर्नबिल (रीयटीसेरस अनडुलाटेस), बरसू-ग्रे वेगटेल (मोटासिला सिनेरेआ), सेहनुंगजूई-वन वेगटेल (मोटाकिला इंडिका), वेरालथी-रेड हेडेड ट्रोगोन (हापैक्टस इरिश्रोसेफालस), थिज़िल-लॉंगटेल ब्रॉडबिल (साइरिसोमस डलहास्य), वेहनग्लै-ग्रे हेडेड पैरोटबिल (पैराडोक्सोर्निस गुलारिस), कोरो-व्हाईट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रस (गररुलैक्स लेउकोफस), चिंगपिरिनु-ब्राउन लकड़ी उल्लू (स्ट्रिक्स लेप्टोग्रामिका), वाहिमिम-लिटिल बटंगुइल (टर्निकस सिल्वाटीका), त्लाकवरह-ब्लू बियरडेड बी ईटर (नीक्वोरोनीस एथर्तौनी), चहेमहूर-ग्रे बैकर्ड लहटोरा (लानीस टेफ़ोनोटस), चुआक-जंगल गाय (कोर्वस मैकक्रोहेंचेस), छिंबुकुई-वन गरुड उल्लू आउल (बुबु निपलेंसिस), मुहिया-लार्ज इंडियन कार्डिट (मिल्वस माइग्रेंस) थेंगवहरबिह-सिलवर्ड ईर्ड मेसिया (लेओथ्रिक्स आर्जेन्टॉरिस), चेंजसेन-मारुन ओरिओल (ओरियोलस ट्रेलिली), ज़ोचाचन-ग्रीन कोकोआ (कोकोआ वायरिडिस) और थ्लैपाव-ग्रे ड्रॉन्गो (डिकरुरुस ल्यूकोफेकस) शामिल हैं;

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीवों की 18 स्थानिक प्रजातियां रहती हैं जिनमें मिशेलिया चमपाका, क्वार्सस एसपीपी, हाइडनोकारपस कुर्जिल, लिंडरा निकुसूआ, टूना सिलिएट, सिनामोमम वेरुम, डायोक्सिलियम गोबारा, फ़िलांथस इम्ब्लिका, मेलोकेन्ना बासीफेरा, हुलांक उतक, कैण्ड लंगुर, सांभर, मुंजक, सामान्य तेंदुआ, बरमेसे अजगर, धनेश, लाल जंगल मुर्गा और सामान्य भारतीय चूहे साँप आदि, शामिल हैं;

और, यह अभयारण्य विभिन्न प्रकार की सीमित वनस्पति, जीवजन्तुओं और पक्षी-जीवों का वास है। यह मिजोरम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के स्थानिक वन्यजीव की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण और आश्रय प्रदान करता है; अतः पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की दृष्टि से इस अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र का संरक्षण और सुरक्षा आवश्यक है ताकि इसकी जैव विविधता एवं पर्यावरण का संरक्षण एवं प्रसार हो सके।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिजोरम राज्य में थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.5 किलोमीटर से 0.8 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र जिसका

क्षेत्रफल 53.07 वर्ग किलोमीटर है, को थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-

- (1) थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.5 किलोमीटर से 0.8 किलोमीटर तक विस्तारित 53.07 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन होगा।
- (2) थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध हैं।
- (3) थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना :-

- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जायेगी, :-
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि और बागवानी ;
 - (iv) पशुपालन और पशु चिकित्सा;
 - (v) भूमि राजस्व और समाधान;
 - (vi) स्थानीय प्रशासन;
 - (vii) पुलिस;
 - (viii) ग्रामीण विकास;
 - (ix) नगरपालिक और शहरी विकास;
 - (x) पंचायती राज;
 - (xi) लोक निर्माण विभाग;
 - (xii) पारि-पर्यटन सहित पर्यटन;
 - (xiii) मत्स्य पालन;
 - (xiv) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(xv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित और अवक्रमित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नदी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।
- (7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्टानुसार निषिद्ध किए गए, विनियमित किए और बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा।
- (8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों से सम्बन्धित उसके कर्तव्यों के निर्वहन का विवरण होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों संबंधी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कृषि भूमि एवं अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा :

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग; सुविधा भण्डार और गृह वास सहित स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों तथा विनियमों एवं क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(च) परंतु यह भी कि वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्र में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में या इनके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के संबंध में सख्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे,:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना, पर्यटन महायोजना के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी

पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात:** - वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाना शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अंतर्गत (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदूषण उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योग भी हैं।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। (ख) परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
10.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और

		<p>नवीकरण;</p> <p>(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग;</p> <p>(iv) कुटीर उद्योग, जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधा भण्डार और पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं जिनमें अंतर्गत ग्रह वास भी हैं; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप।</p> <p>(ग) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	<p>फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।</p>
13.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि अथवा सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।

17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाने जैसे क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिस्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति.-

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक निगरानी समिति (डीईएसजेडएमसी) गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

(i)	संबंधित उपायुक्त	-अध्यक्ष;
(ii)	भूमि राजस्व और बंदोबस्त विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iii)	ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iv)	कृषि विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(v)	स्थानीय प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vi)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(viii)	मत्स्य विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(ix)	उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(x)	पुलिस विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xi)	ऊर्जा एवं विद्युत विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xii)	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xiii)	मृदा एवं नदी संरक्षण विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xiv)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xv)	पर्यावरण संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे मिजोरम सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	-सदस्य;
(xvi)	क्षेत्रीय अधिकारी, मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-सदस्य;

(xvii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का विशेषज्ञ	—सदस्य;
(xviii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से जैव-विविधता का विशेषज्ञ	—सदस्य;
(xix)	संबंधित डीसीएफ / डीएफओ	—सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय :-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनः गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
- (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा.सं. 25/18/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

- उत्तर:** यह सीमा मर लुई (92°27'41.28"पू, 23°23'48.198"उ) से आरंभ होकर अभयारण्य की सीमा से 600 मीटर दूर तक विस्तृत है। यह सेकैम लुई के साथ पूर्व की ओर जाकर तुत लुई (92°33'49.675"पू, 23°22'26.454" उ) से मिलती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 600 मीटर दूर जवेलपुई लुई की शुरुआत से तुत लुई तक है।
- पूर्व:** तुत लुई से पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर की ओर 800 मीटर तक विस्तृत है और तुईदम लुई (92°34'43.744"पू, 23°20'14.488" उ) को पार करके और तुत लुई के साथ जाती है और तुईथुर लुई को पार करके लौंगपाव लुई (92°30'9.266" पू, 23°14'8.436" उ) से मिलती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 800 मीटर दूर तुत लुई से लौंगपाव लुई तक है।
- दक्षिण:** लौंगपाव लुई से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तुत लुई के साथ 500 मीटर तक विस्तृत है और सेथला लुई के साथ कौ लुई को पार करती है और बेतियांग लुई (92°31'15.976"पू, 23°12'43.466"उ) से मिलती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 500 मीटर दूर लौंगपाव लुई से बेतियांग लुई तक है।
- पश्चिम:** यह बेतियांग लुई से पोलेहैलैंग लुई (92°30'9.266" पू, 23°14'8.436" उ) और दाईदुक लुई को पार करके उत्तर की ओर जाती है और यह लंगफम लुई (92°29'24.061" पू, 23°17'38.398" उ) के साथ जाती है और ज़ागगेक लुई की ओर जाकर और यह तुईखवी लुई के साथ अभयारण्य सीमा के साथ बाहर की ओर जाती है और सेतैल लुई (92°28'57.479" पू, 23°17'19.434"उ) और नुथलवी लुई (92°28'2.185" पू, 23°18'11.775" उ) को पार करती है। यह मर लुई के साथ उत्तर की ओर जाती है तथा हौहुक लुई को पार करके 500 मीटर दूर जहाँ मर लुई और जवलपुई लुई मिलती है। बेतियांग लुई से मर लुई और जवलपुई लुई के जोड़ बिंदु तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 500 मीटर है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 500 मीटर से 800 मीटर तक विस्तृत है।

उपाबंध-II

भू स्थिति प्रणाली की दृष्टि से थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक
संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांक

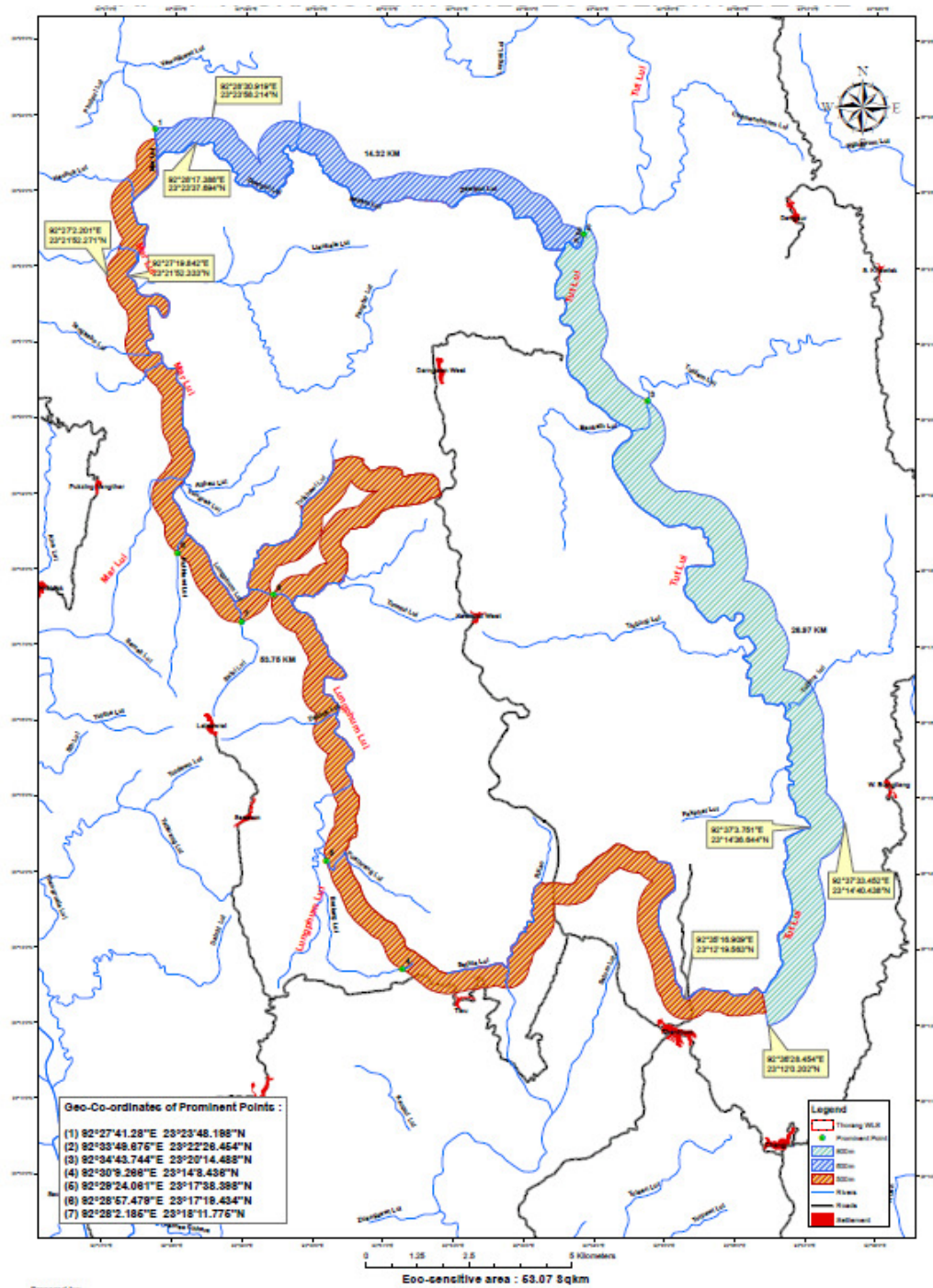
क्र. सं.	अवस्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	उत्तर	23°23'37.694" उ	92°28'17.388" पू
2	दक्षिण-पूर्व	23°14'36.644" उ	92°37'3.751" उ
3	दक्षिण	23°12'19.563" उ	92°35'16.909" उ
4	उत्तर-पश्चिम	23°21'52.333" उ	92°27'19.842" उ

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अवस्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	उत्तर	मर लुई	23°23'48.198"उ	92°27'41.280"पू
2	उत्तर-पूर्व	तुत लुई	23°22'26.454"उ	92°33'49.675"पू
3	पूर्व	तुईडैम लुई	23°20'14.488"उ	92°34'43.744"पू
4	दक्षिण	बेतियांग लुई	23°12'43.466"उ	92°31'15.976"पू
5	दक्षिण-पश्चिम	पुआलहरैंग लुई	23°14'8.436"उ	92°30'9.266"पू
6	पश्चिम	लुंगफुम लुई	23°17'38.398"उ	92°29'24.061"पू
7	पश्चिम	सैतेल लुई	23°17'19.434"उ	92°28'57.479"पू
8	पश्चिम	नुथलावी लुई	23°18'11.775"उ	92°28'2.185"पू

उपाबंध-III

भू-निर्देशांकों के साथ थोरांगतलांग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



Prepared by:
GIS Cell SPSC Dept Mizoram

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2018

S.O. 229(E).—The following Draft of Notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said Draft Notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the Draft Notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or send it to the e-mail address of the Ministry at eszmef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Thorangtlang Wildlife Sanctuary is situated at Lunglei District in Mizoram covering an extent of 180.0 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary falls within the sub-tropical region and enjoy sub-tropical climate with annual rainfall ranging from 1700 mm to 3900 mm. Most of the area is hilly terrain, except the valleys and foothills, with 70% steep to very steep slopes and 30% of gentle slope with sandy clay soil and sedimentary rocks;

AND WHEREAS, the Sanctuary was declared by the State Government of Mizoram considering its ecological, floral, faunal and natural significance, and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 vide Notification No. B.12012/24/2014-FST dated the 2nd November, 2015;

AND WHEREAS, the Sanctuary is tremendously rich in biodiversity, and provides shelter and protection to many rare, endangered and threatened (RET) and endemic species;

AND WHEREAS, the Sanctuary conserves and supports about 48 species of flora including 32 tree species, 9 shrub species, 2 species of bamboo and rattans, and 5 species of orchids. The 32 tree species include Arda (*Pithecolobium bigeminum*), Khawitur (*Dryptes lancifolia*), Saper (*Lindera nacusua*), Tiar (*Saurania punduana*), Thingpuithing (*Lithocarpus elegans*), Saphut (*Randia wallichii*), Thingsia (*Castanopsis lanceafolia*), Then (*Quercus helferiana*), Herhse (*Mesua ferrea*), Tei pui (*Toona ciliate*), Thakthing (*Cinnamomum verum*), Sentezel (*Calophyllum palyanthum*), Thinglung (*Elacocarpus floribundus*), Ngalhchhun (*Eriobotrya bengalensis*), Tespata (*Cinnamomum tamala*), Zathuhang (*Polyalthia Jenkinsii*), Thingthupui (*Dysoxylum Gobara*), Thei kel ek (*Elaeocarpus aristatus*), Hnah thap pa (*Colonafla grocarpa*), Char (*Terminalia myriocarpa*), Mualhawih (*Saraca asoca*), Pa khat (*Actinodaphe-odorata*), Suktlawng (*Mammea suriga*), Hmar hleng (*Styrax serrulatum*), Lenhmui (*Syzygium cumini*), Thei kum (*Diospyros malabarica*), Theihlei khak (*Amoora chittagonga*), Beraw (*Canarium strictum*), Banphar (*Anthocephalus chinensis*), Thingkhim (*Acer laevigatum*), Haifavang (*Mangifera sylvatica*) and Tuairam (*Terminalia crenulata*). The 9 shrub species include Zawngtenawhlung (*AlchorneaTiliaefolia*), Phaktel (*Bridelia monoica*), Keltebengbeh (*Tabernaemontana divaricata*), Pelh (*Gnetum Gnemon*), Arngeng (*Maesa indica*), Kawlkar (*Leea indica*), Chhawntan (*Fagerlindia fasciculate*), Lum (*Morinda Angustifolia*) and Naunuar (*Ardisia paniculata*). The 2 species of bamboo include Mau tak (*Melocanna baccifera*) and Sairil (*Dinochloa campactiflora*). The 5 species of orchids include Senhri (*Renanthera imschootiana*), Ban sei/Laihang (*Dendrobium fimbriatum*), Lawh lei (*Vanda coerulea*), Nauban par var (*Coelogyne nitida*) and Nauban-nawinaw (*Pleione praecox*);

AND WHEREAS, the Sancturay supports 18 fauna species including 4 species of carnivores, 2 species of ungulates, 3 omnivores species, 4 species of primates and 3 other species of small mammals including common Leopard (*Panthera parades*), Golden cat (*Catpuma Temmincki*), Jungle cat (*Felis chaus*), Leopard cat (*Prionailurus Bengalensis*), Barking deer (*Muntiacus muntjak*), Serow (*Naemorhedus Sumatraensis*), Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), Jackal (*Canis aureus*), Wild dog (*Cuon alpines*), Capped langur-Ngau (*Presbytis pileatus*), Hoolock gibbon-Hauhuk- (*Hylobate hoolock*), Slow lorries (*Nycticebus bengalensis*), Phayre's leaf monkey (*Trachypithecus pileatus*), Himalayan Crestless porcupine-Sakuh (*Hystrix brachyuran*), Malayan giant squirrel-Awrrang (*Ratufa bicolor*), Himalayan stripped squirrel (*Tamiops macclellandi*), Mountain Tortoise (*Manouria emys*) and Burmese Python (*Phyton molurus*);

AND WHEREAS, the Sanctuary is rich in avifauna and supports 38 important bird species like Tehhek-Black chinned Yuhina (*Yuhina nigrimenta*), Daikat-Golden Headed Tailorbird (*Orthotomus cucullatus*), Thlekbur-Large wood Shrike (*Tephrodornis Virgatus*), Bawng-Yellow throated Minivet (*Piricrocotus solaris*), Irliak/Bawngpui-Large cuckoo-Shrike (*Coracina novae-hollandiea*), Thlohssai-Great Slaty Woodpecker (*Mulleripicus pulverulentus*), Suklet-Velvet-fronted Nutchatch (*Sitta frontalis*), Suklet-Whitetailed Nutchatch (*Sitta himalayansis*), Luangtubeuh-Specllet Piculet (*Picummus innominatus*), Vasir-Grey Sibia (*Heterophasia gracilis*), Zova-Striped laughing thrush (*Garrulax virgatus*), Vabak-Hodgson's Frogmouth (*Batrachestomus hodgsoni*), Zochippui-Grey winged Blackbird (*Turdus bulbul*), Tep-Himalayan Green finch (*Carduelis spinoides*), Hnahfun-Golden headed Tailor Bird (*Orthotomus cucullatus*), Tahngai-Bay Owl (*Phodilus badius*), Hmunchhe-Arpui Pigmy Wren-Babbler (*Pnoepyga pusilla*), Valambawk-Great eared Mightjar (*Eurostopodus macrotis*), Lengder-Ashy swallow-shrike (*Artamus fuscus*), Vamur-Palm shift (*Cypsiurus parvus*), Kawlhawk-Wreathed hornbill (*Rhyticerus undulates*), Bursu-Grey wagtail (*Motacilla cinerea*), Sehnungzui-Forest wagtail (*Motacilla indica*), Varalhti-Red headed Trogon (*Harpactes erythrocephalus*), Thizil-Longtailed Broadbill (*Psarisomus dalhousiae*), Vahnanghlai-Grey headed Parrotbill (*Paradoxornis gularis*), Koro-White crested laughing thrush (*Garrulax leucolophus*), Chingpirinu-Brown wood owl (*Strix leptogrammica*), Vahmim-Little buttoanguail (*Turnix sylvatica*), Tlakawrh-Blue bearded Bee

eater (*Nyctyornis athertoni*), Chhemhur-Grey backed shrike (*Lanius tephronotus*), Choak-Jungle crow (*Corvus macrorhynches*), Chhimbukpui-Forest Eagle Owl (*Bubo nipalensis*), Muchhia-Large Indian Kite (*Milvus migrans*), Thlangvabarbeh-Silvered eared Mesia (*Leiothrix argentauris*), Changsen-Maroon Oriole (*Oriolus trailii*), Zovachan-Green Cochoa (*Cochoa viridis*) and Thlapawl-Grey Drongo (*Dicrurus leucophaecus*);

AND WHEREAS, the Sanctuary also have 18 endemic species of flora and fauna including *Michelia champaca*, *Quercus* spp., *Hydnocarpus kurzii*, *Lindera nacusua*, *Toona ciliate*, *Cinnamomum verum*, *Dysoxylum gobara*, *Phyllanthus emblica*, *Melocanna baccifera*, Hoolock gibbon, Capped langur, Sambar, Barking deer, Common leopard, Burrrrmese python, Hornbill, Red jungle fowl and Common Indian rat snake;

AND WHEREAS, the Sanctuary is home to a variety of confined flora, fauna and avifauna, and provides protection and shelter to rare and endangered species of wildlife endemic to Mizoram and the North-East region. Hence, it is necessary to conserve and protect the area around the Sanctuary from ecological and environmental point of view to protect and propagate the biodiversity therein and its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 53.07 square kilometers with extents varying from 0.5 km to 0.8 km around the boundary of Thorangtlang Wildlife Sanctuary in Mizoram State as the Thorangtlang Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-Sensitive Zone), details of which are as under, namely :-

1. Extent and Boundaries of Eco-Sensitive Zone :-

- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be 53.07 square kilometers with extents varying from 0.5 km to 0.8 km around the boundary of the Thorangtlang Wildlife Sanctuary;
- (2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Thorangtlang Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I**;
- (3) The coordinates of the Thorangtlang Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone in terms of Global Positioning System coordinates is appended as **Annexure-II**;
- (4) The map of Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-III**;

2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone :-

- (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.
- (2) The Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this Notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments for integrating the ecological and environmental considerations into the proposed plan:
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture & Horticulture;
 - (iv) Animal Husbandry and Veterinary;
 - (v) Land Revenue and Settlement;
 - (vi) Local Administration;
 - (vii) Police;
 - (viii) Rural Development;
 - (ix) Municipal and Urban development;
 - (x) Panchayati Raj;

- (xi) Public Works Department;
- (xii) Tourism including Eco-tourism;
- (xiii) Fisheries;
- (xiv) Irrigation and Flood Control;
- (xv) State Pollution Control Board.

- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this Notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of the local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as park and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies. The Zonal Master Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote the eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the State and District level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this Notification.

3. **Measures to be taken by State Government :-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this Notification, namely :-

(1) Landuse:

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) Small scale industries not causing pollution;
 - (iv) Cottage industries including village industries; Convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - (v) Promoted activities and activities given under para 4.
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority the relevant laws of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Provided also that there shall be no consequential reduction in the green area such as forest area and agriculture area. Efforts shall be made to reforest the unused, denuded or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies: The catchment areas of all natural rivers/channels/springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan. The strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism:

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1.0 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or up to the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of 1.0 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
- (ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
- (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites: Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as a part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution: Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the

Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes: Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

- (a) The solid waste disposal and management in Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide Notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016;
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste: Bio-medical waste management shall be as under:

- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management: The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management: The management of construction and demolition waste in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste Management: The e- waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution: The prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units: (i) On or after the publication of this Notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this Notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone:

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in Feb 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.

7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>(a) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within 1.0 km of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.</p> <p>(b) Provided that, beyond 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism/Eco-tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies .	Regulated under applicable laws.
11.	Construction activities.	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>(b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <p>(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;</p> <p>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</p> <p>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;</p> <p>(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and</p> <p>(v) Promoted activities listed in this Notification.</p> <p>(c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(d) Beyond 1.0 km it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing

		products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law.Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, Microlites, helicopter, drones etc.	Regulated under applicable law.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of plastic bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.

C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Biogas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of habitat/ degraded land/ forests.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee :- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a District level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee (DESZMC) for effective monitoring of the Eco-Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

- | | |
|---|-------------|
| (i) Deputy Commissioner concerned | - Chairman; |
| (ii) Representative of Land Revenue & Settlement Department | - Member ; |
| (iii) Representative of Rural Development Department | - Member ; |
| (iv) Representative of Agriculture Department | - Member ; |
| (v) Representative of Local Administration Department | - Member ; |
| (vi) Representative of Public Works Department | - Member ; |
| (vii) Representative of Public Health Engineering | - Member ; |
| (viii) Representative of Fishery Department | - Member ; |
| (ix) Representative of Industries Department | - Member ; |
| (x) Representative of Police Department | - Member ; |
| (xi) Representative of Power & Electricity Department | - Member ; |
| (xii) Representative of Animal Husbandry & Veterinary Department | - Member ; |
| (xiii) Representative of Soil & Moisture Conservation Department | -Member ; |
| (xiv) Representative of Minor Irrigation Department | - Member ; |
| (xv) Representative of non-governmental organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Mizoram | - Member ; |
| (xvi) Regional Officer, Mizoram State Pollution Control Board | - Member ; |
| (xvii) One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram | - Member ; |
| (xviii) One expert in Biodiversity from reputed institution or university of the State | - Member ; |

- of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram
- (xix) Concerned DCF/DFO -Member
Secretary.

6. Terms of Reference.-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
 - (2) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said Notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this Notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma appended at Annexure IV.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this Notification.
 8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/18/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I**Boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Thorangtlang Wildlife Sanctuary**

NORTH: Starting from Mar lui (92°27'41.28"E, 23°23'48.198"N) extending up to 600 meters away from the sanctuary boundary it goes east ward along Sekam lui meeting Tut lui (92°33'49.675"E, 23°22'26.454"N). The width of the Eco-Sensitive Zone from the origin of Zawlpui lui to Tut lui is 600 meters away from the Sanctuary boundary.

EAST: From Tut lui the Eco-Sensitive Zone boundary extend to 800 meters going North and crosses Tuidam lui (92°34'43.744"E, 23°20'14.488"N) and going along Tut lui and crossing Tuithur lui and meets Luangpaw lui (92°30'9.266"E, 23°14'8.436"N). The width of the Eco-Sensitive Zone from Tut lui to Luangpaw lui is 800 meters away from the Sanctuary boundary.

SOUTH: From Luangpaw lui the Eco-Sensitive Zone boundary goes along Tut lui at an extend of 500 meters and crossing Kau lui going along Sethla lui and meets Betiang lui (92°31'15.976"E, 23°12'43.466"N). The width of the Eco-Sensitive Zone from Luangpaw Lui to Betiang lui is 500 meters away from the Sanctuary boundary.

WEST: From Betiang lui it goes North crossing Pualhrang Lui (92°30'9.266"E, 23°14'8.436"N) and Daiduk Lui and it goes along Lungphum Lui (92°29'24.061"E, 23°17'38.398"N) and goes in towards Zawngek Lui and the it curves out along the sanctuary boundary along Tuikhawi Lui and cross Satel lui (92°28'57.479"E, 23°17'19.434"N) and Nuthlawi Lui (92°28'2.185"E, 23°18'11.775"N) it goes North along Mar Lui and crosses Hauhuk Lui and meets where Mar lui and Zawlpui Lui Join at 500 meters. The width of the Eco-Sensitive Zone from Betiang Lui to the joining point of Mar Lui and Zawlpui Lui is 500 meters away from the Sanctuary Boundary.

The width of the Eco-Sensitive Zone varies from 500 meters to 800 meters from the Sanctuary boundary.

ANNEXURE-II**Coordinates of the Thorangtlang Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone in terms of Global Positioning System****GEO-COORDINATES OF THE PROTECTED AREA BOUNDARY**

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	North	23°23'37.694"N	92°28'17.388"E
2	South-East	23°14'36.644"N	92°37'3.751"E
3	South	23°12'19.563"N	92°35'16.909"E
4	North-West	23°21'52.333"N	92°27'19.842"E

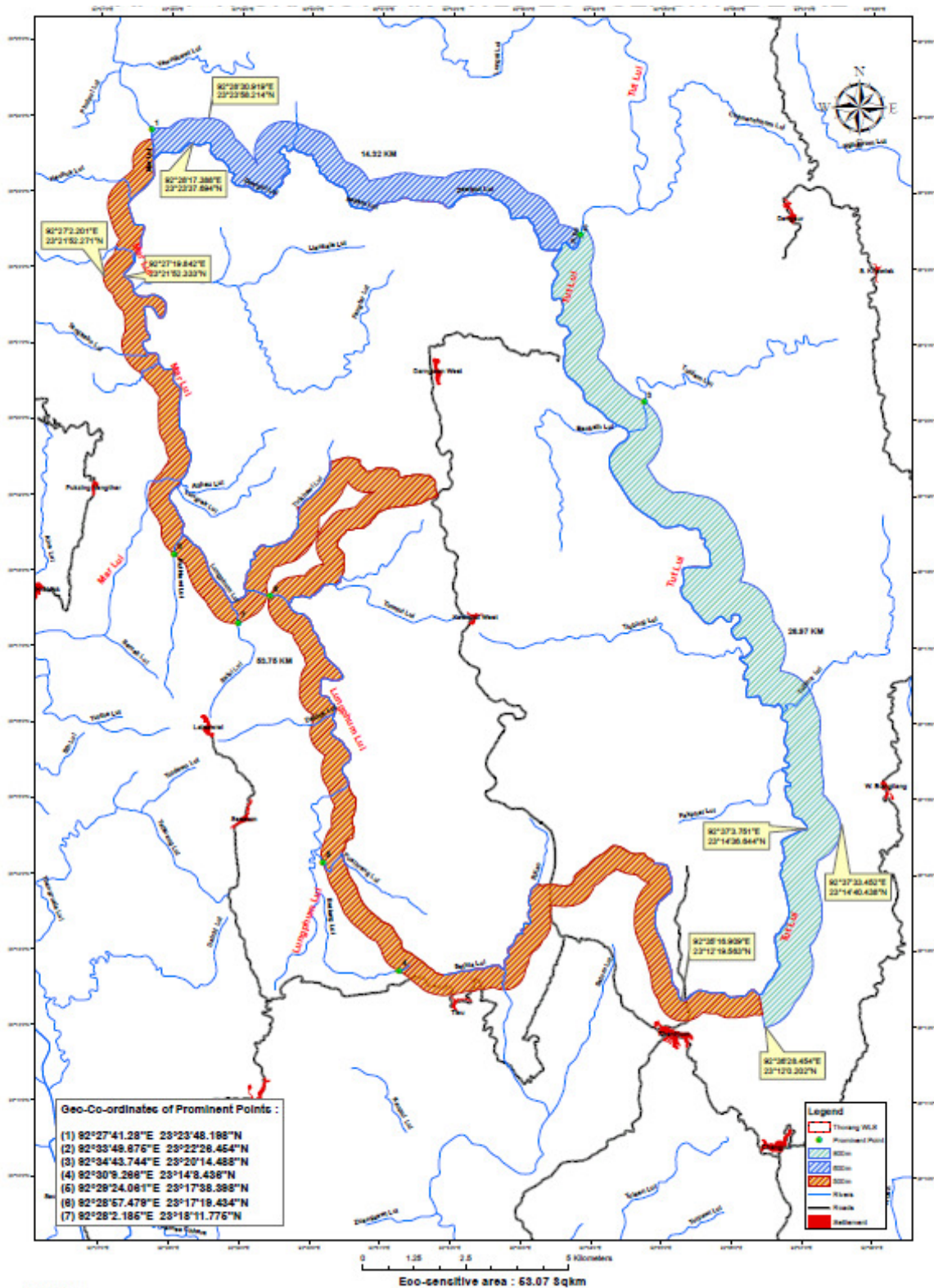
GEO-COORDINATES OF THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	North	Mar Lui	23°23'48.198"N	92°27'41.280"E
2	North-East	Tut Lui	23°22'26.454"N	92°33'49.675"E
3	East	Tuidam Lui	23°20'14.488"N	92°34'43.744"E
4	South	Betieng Lui	23°12'43.466"N	92°31'15.976"E
5	South-West	Pualhrang Lui	23°14'8.436"N	92°30'9.266"E
6	West	Lungphum Lui	23°17'38.398"N	92°29'24.061"E

7	West	Satel Lui	23°17'19.434"N	92°28'57.479"E
8	West	Nuthlawi Lui	23°18'11.775"N	92°28'2.185"E

ANNEXURE-III

MAP OF THE THORANGLANG WILDLIFE SANCTUARY ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES



ANNEXURE-IV**Pro forma of Action Taken Report: Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee:-**

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: (Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: (Details may be attached as separate Annexure)
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance